क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 18 | सितम्बर 16-30, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-4

11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी पर :

दुनिया पर अपनी दादागिरी क़ायम रखने के लिए अमरीकी-साम्राज्यवाद की अपराधी योजना

ऐसे समय पर, जब अमरीकी नेता "नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" को बनाए रखने का दिखावा कर रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है कि सर्व सम्मति से स्थापित किये गए नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों का उल्लंघन करने के अमरीका के कारनामों के इतिहास को फिर से देखा जाए। यह भी जानना ज़रूरी है कि अमरीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन अत्यधिक आक्रामक और सुनियोजित तरीके से, विशेष रूप से 2001 के बाद से, लगातार जारी है।

11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन-टावरों पर दो हवाई जहाजों के टकराने के बाद लगभग 3,000 लोग मारे गए थे और तीसरा विमान वाशिंगटन में पेंटागन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस आतंकवादी हमले का इस्तेमाल, अमरीका द्वारा एक के बाद दूसरे स्वतंत्र राज्य के ख़िलाफ़ सशस्त्र आक्रमण शुरू करने को सही ठहराने के लिए किया गया था। वे सभी आक्रमण एक वैश्विक "आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध" के साइनबोर्ड के तहत किये जाते रहे हैं।

अफ़ग़ानिस्तान

9/11 के हमले के तुरंत बाद, अमरीकी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि वह अफ़ग़ान-सरकार के समर्थन से, अल-कायदा नामक एक इस्लामी आतंकवादी-गुट द्वारा रची गई साज़िश थी। वह साज़िश की कहानी अमरीकी प्रचार मशीन द्वारा, बिना किसी सबूत के फैलायी गयी थी। उसी प्रचार का इस्तेमाल करके, 7 अक्टूबर को अमरीकी और ब्रिटिश सैनिकों ने अफ़ग़ानिस्तान पर सशस्त्र आक्रमण शुरू किया और उसके बाद विदेशी सैनिकों ने अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया।

अफ़ग़ानिस्तान पर आक्रमण, 9/11 आतंकवादी हमले के ठीक 26 दिन बाद शुरू हुआ था। कई अमरीकी पूर्व सेनानियों ने बताया है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर युद्ध-प्रयास को इतने कम समय में तैयार नहीं किया जा सकता था और उसे अंजाम नहीं दिया जा सकता था। उसकी तैयारी बहुत पहले ही शुरू हो गयी होगी। 9/11 की घटनाओं ने पहले से ही बनायी गयी योजना को लागू करने का बहाना प्रदान किया। अफ़ग़ानिस्तान पर सशस्त्र कब्ज़ा अगले 20 वर्षों तक जारी रहा। अनुमान है कि इस अवधि में, 2001-2021 के दौरान 2,43,000 लोगों की मौत हुई।

पिछले 21 वर्षों के दौरान, दुनिया के विभिन्न देशों में विनाशकारी युद्धों के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद ज़िम्मेदार है। यह वही राज्य है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, सर्व-सम्मति से स्थापित किये गए राज्यों के आपसी संबंधों के हर नियम और मानदंड का बार-बार उल्लंघन किया है।

इराक

अमरीका ने दावा किया था कि उसके खुफिया सूत्रों के अनुसार, सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाली इराक सरकार के पास "जन सामूहिक विनाश के हथियार" हैं। अब बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने आ चुका है कि वह एक जानबूझकर फैलाया गया सफेद झूठ था। उसका इस्तेमाल, 20 मार्च, 2003 से शुरू किये गए, इराक पर एक सशस्त्र आक्रमण को सही ठहराने के लिए किया गया था। उस हमले को अमरीका के नेतृत्व वाले आक्रमणकारियों के एक गुट द्वारा किया गया था, जिन्होंने खुद को 'रज़ामंद देशों का गठबंधन' का नाम दिया था। इराक पर अमरीका के नेतृत्व वाले युद्ध और इराक पर कब्ज़े के कारण, 2003-2011 के दौरान 4,00,000 से अधिक लोगों की मौत होने का अनुमान है।

न तो अफ़ग़ानिस्तान पर सशस्त्र आक्रमण और न ही इराक पर सशस्त्र आक्रमण को, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति प्राप्त थी।

शेष पृष्ठ 2 पर

अमरीकी साम्राज्यवाद की रणनीति में हिन्दोस्तान की भूमिका

अमरीकी साम्राज्यवाद की पूरे एशिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की रणनीति में हिन्दोस्तान प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

अमरीकी विदेश विभाग में पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के मामलों के ब्यूरो के उप सहायक सचिव, एलेक्स वोंग ने अप्रैल 2018 में "इंडो-पैसिफिक रणनीति" के विषय पर दिये गये एक भाषण में निम्नलिखित बातें रखीं :

"इंडो-पैसिफिक" शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं । इससे पहले, लोग एशिया-पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करते थे ... लेकिन हमने इन शब्दों को दो कारणों से अपनाया है, और यह दो कारणों से महत्वपूर्ण है। नंबर एक, यह ... इस वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करता है कि दक्षिण एशिया और विशेष रूप से हिन्दोस्तान, पैसिफिक और पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ... दूसरा, यह हमारे हित में है, अमरीका के हित में है, श कि हिन्दोस्तान इस क्षेत्र में तेज़ी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह एक ऐसा देश है जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र और खुली व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है और संभाल सकता है और हमारी नीति है यह सुनिश्चित करना कि हिन्दोस्तान उस भूमिका को निभाए।"

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का मतलब है हिन्द महासागर व प्रशांत महासागर का क्षेत्र। इसमें अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमरीका के पश्चिमी तट तक के पूरे क्षेत्र के सभी देश शामिल हैं। हिन्दोस्तान और अमरीका इसके दो छोर (पश्चिम में हिन्दोस्तान और पूर्व में अमरीका) बनने वाले हैं। हिन्दोस्तान की भूमिका है अमरीका को एशिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सहायता करना।

अमरीका यह मांग कर रहा है कि सभी देशों को इजारेदार पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा अप्रतिबंधित लूट के लिए अपने दरवाज़े खोल देने चाहिएं और बहुपार्टीवादी प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र के नुस्खे का पालन करना चाहिए। जो देश ऐसा नहीं करते हैं, उन पर "स्वतंत्र और खुला" नहीं होने का आरोप लगाया जाता है।

एडमिरल जॉन एक्विनिलो ने, मई 2018 में अमरीका-पैसिफिक नौसेना की कमान संभालने पर घोषणा की थी कि : "बड़ी-बड़ी ताक़तों की आपसी प्रतिस्पर्धा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से ज्यादा और कहीं भी नहीं हैं ..."।

अमरीका ने अपनी एशिया-धुरी की नीति के तहत, अपनी सेनाओं का अधिकतम हिस्सा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में अमरीका ने अपने सशस्त्र बलों की तैनाती में तेज़ी से वृद्धि की है और वह चीन के द्वीपों से 12 मील की दूरी के अंदर सुनियोजित तरीके से 'फ्रीडम ऑफ़ नेविगेशन (नौसंचार की स्वतंत्रता)' नामक युद्ध अभ्यासों को नियमित तौर पर करता रहता है। ये चीन को उकसाने की कोशिशें हैं। ये चीन और हिन्दोस्तान समेत कई अन्य देशों द्वारा माने जाने वाले उस क़ानून का उल्लंघन हैं, जिसके अनुसार युद्ध पोतों को किसी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, उस देश से अनुमति लेनी होती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को उस देश की तटरेखा से 200 कि.मी. की दूरी तक के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। अमरीका हिन्दोस्तान और अन्य देशों को चीन के ख़िलाफ़ भड़काता रहा है।

हिन्दोस्तान के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 18 अगस्त को, बैंकाक, थाईलैंड के चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण में कहा था कि : "... हिन्दोस्तान के हितों का बहुत बड़ा हिस्सा अब हिन्दोस्तान के पूर्व में, हिंद महासागर से आगे और प्रशांत महासागर क्षेत्र में है।" इससे आगे, उन्होंने कहा कि, "सीधे शब्दों में कहें तो हिंद महासागर से प्रशांत महासागर का अलग होना 1945 से चल रहे, अमरीकी रणनीतिक प्रभुत्व का सीधा परिणाम था। चूंकि पिछले दो दशकों में अलग-अलग देशों की ताक़तों में परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इसमें भी बदलाव होना अनिवार्य है। अमरीका की वर्तमान नयी स्थिति, चीन के साथ-साथ हिन्दोस्तान का उभर कर आगे आना, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र से बढ़ते बाहरी सम्बन्ध, दक्षिण कोरिया के व्यापक हितों और वास्तव में, आसियान के व्यापक दृष्टिकोण, इन सभी ने इस परिवर्तन में योगदान दिया है। ... अब किसी एक देश के लिए इस सबतरफ़ा बोझ को संभालना संभव नहीं है।"

मंत्री महोदय का तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिन्दोस्तान को अमरीकी साम्राज्यवाद के 'बोझ' को उठाने में हिस्सेदार बन जाना चाहिए।

शेष पृष्ठ 4 पर

अंदर पढ़ें

■ हिन्दोस्तान के विभाजन के पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवादी रणनीति 3

11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी पर ...

पृष्ठ 1 का शेष

दुनिया के कई देशों और लोगों ने उसका विरोध किया था। परन्तु, दोनों ही मामलों में, अमरीका ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी मान्य नियमों का उल्लंघन किया और राष्ट्रों के आत्मनिर्धारण के अधिकार को कुचल कर विश्व स्तर पर, बड़े पैमाने पर, लोगों की मृत्यु और विनाश को अंजाम दिया।

लीबिया

मार्च 2011 में, अमरीका और उसके सभी नाटो सहयोगियों ने लीबिया पर बम बरसाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। ऐसा प्रचार किया गया था कि लीबिया के अन्दर गद्दाफी के तथाकथित दुष्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रही विद्रोही ताक़तों के समर्थन में ऐसा किया गया था। लीबिया की सरकार को मानव अधिकारों का हनन करने वाले के रूप में पेश करने के लिए एक विशाल विश्वव्यापी अभियान शुरू किया गया था। उसमें लीबिया के सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार और अपने ही नागरिक समूहों पर गोली चलाने की फर्जी वीडियो क्लिपें शामिल थीं।

विद्रोही बलों का सैन्य कमांडर एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने सी.आई.ए. के सहयोग से, गद्दाफी को गिराने के लिए, सशस्त्र दलों को प्रशिक्षित करने के लिए, अमरीका के वर्जीनिया राज्य में एक तथाकथित लिबियन नैशनल आर्मी की स्थापना की थी।

नाटो के सुरक्षा बलों ने लीबिया और उसकी जनता पर सात महीने से अधिक समय तक बमबारी करके, मौत और तबाही फैलाई थी। उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों, राजमार्गों, दूरसंचार नेटवर्क, साथ ही सिंचाई और पेयजल नेटवर्क को बेरहमी से नष्ट कर दिया। अक्टूबर 2011 में, उन्होंने कर्नल गद्दाफी को पकड़ लिया और बिना किसी मुकदमे के, उन्हें बेरहमी से मार डाला।

गद्दाफी की सरकार का उस तरह से उखाड़ फेंका जाना लीबिया के लोगों के अपने भविष्य का निर्धारण करने के अधिकार का घोर उल्लंघन था। साम्राज्यवादी ताक़तों द्वारा समर्थित हथियारबंद गिरोहों ने लीबिया के संसाधनों को लूट कर आपस में बांटने की कशिश करते हुए, लीबिया में अराजकता फैला दी। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य साम्राज्यवादी देशों की इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों ने, लीबिया के तेल–संसाधनों – जो दुनिया में सबसे समृद्ध माने जाते थे – पर और उस देश के तेल उद्योग के सभी प्रतिष्ठानों पर कब्ज़ा कर लिया।

सीरिया

लीबिया पर बेरहम हमला, कब्ज़ा और लूट करने के साथ–साथ, अमरीका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी गठबंधन ने, सीरिया के भीतर एक गुप्त अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने बशर अल–असद की सरकार को गिराने और वहां पर अमरीका के नियंत्रण में काम करने वाली सरकार को बिठाने के उद्देश्य से, विपक्षी ताक़तों को धन और हथियार दिए। अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर झूठा प्रचार किया कि सीरिया की सरकार अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ रसायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है।

सितंबर 2014 में, अमरीकी और ब्रिटिश लड़ाकू जेट विमानों ने, सीरिया पर बम बरसाए। वह एक ऐसी कार्रवाई थी जो सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन था। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों में से एक यह है कि जब सुरक्षा परिषद किसी भी मामले पर विचार कर रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य देश को, युद्ध शुरू करने की अनुमति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, सीरिया पर हमला करने की अमरीका की मांग पर रोक लगा दी थी। परन्तु अमरीका ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने के बहाने, सीरिया पर आक्रमण किया था।

अप्रैल 2018 में, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर मिसाइल हमले किए। लगभग पूरे एक दशक तक, इन साम्राज्यवादी ताक़तों के अवैध हस्तक्षेप की वजह से सीरिया में लम्बे समय तक गृह युद्ध चलता रहा है, जिसमें लाखों बेकसूर लोगों की जान गई है। पूरे–पूरे शहरों और ग्रामीण इलाकों को तबाह कर दिया गया है। इसके कारण सीरिया से लाखों–लाखों लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद की रणनीति और हथकंडे

अमरीकी साम्राज्यवाद की रणनीति का उद्देश्य एक ओर तो सच्ची जन–क्रान्ति को रोकना है, और दूसरी ओर अपने आधिपत्य के रास्ते में आड़े आने वाले किसी भी राज्य को कमजोर और बर्बाद करना है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने दो प्रमुख हथकंडे विकसित किए हैं और उनका विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया है। एक है गुप्त रूप से आतंकवाद को प्रश्रय देना और खुले तौर पर आतंकवाद के ख़िलाफ़ तथाकथित युद्ध को छेड़ना। दूसरा, तथाकथित लोकतंत्र–समर्थक और भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलनों का आयोजन करना है।

अमरीका और उसकी खुफिया एजेंसियां उन विभिन्न आतंकवादी गिरोहों के मूल निर्माता थे, जिन्हें उन्होंने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत कब्ज़ाकारी सैनिकों से लड़ने के लिए धन और हथियार दिए थे। 1989 में, सोवियत सेना के उस देश से हटने के बाद, विभिन्न देशों में अमरीकी साम्राज्यवाद के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन आतंकवादी गिरोहों का इस्तेमाल किया गया था।

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से जाना जाने वाला, आतंकवादी गिरोह तब मशहूर हो गया, जब यू ट्यूब पर एक वीडियो क्लिप को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिसमें दिखाया गया कि एक अमरीकी पत्रकार का सर काटा जा रहा है। बाद में फॉरेंसिक रूप से साबित हुआ कि वह वीडियो क्लिप फ़र्ज़ी था और किराए के अभिनेताओं का इस्तेमाल करके बनाया गया था।

गुप्त रूप से आतंकवादी हरकतों का आयोजन करने और उन्हें स्वतंत्र देशों पर कब्ज़ा करने के जंग को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करने के साथ–साथ, विभिन्न तथाकथित रंगीन–क्रांतियों में युवाओं को सड़कों पर लाने के लिए, सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। इनमें यूक्रेन में नारंगी–क्रांति, ट्यूनीशिया में जैस्मीन–क्रांति, मिस्र में कमल–क्रांति, जॉर्जिया में गुलाब–क्रांति और किर्गिस्तान में ट्यूलिप–क्रांति शामिल हैं। गौर करने की ज़रूरत है कि हर ऐसी तथाकथित क्रांति के परिणामस्वरूप, उस देश में एक अमरीका–परस्त शासन की स्थापना हुई है।

निष्कर्ष

11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमले के बाद से, पिछले 21 वर्षों की हक़ीक़त ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि आतंकवाद और तथाकथित आतंकवाद पर जंग, दोनों ही, अमरीकी साम्राज्यवाद के हथकंडे हैं – उसकी प्रधानता को बरकरार रखने और उसके हुक्म तले एक ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने के उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए ।

अफ़ग़ानिस्तान और इराक के सशस्त्र कब्ज़े की वजह से, एशिया के तेल–समृद्ध क्षेत्रों में, अमरीकी प्रभाव–क्षेत्र का विस्तार हुआ है। ईरान को पूर्व और पश्चिम से घेरा गया है। इराक और लीबिया के विनाश ने, अमरीकी डॉलर की बजाय यूरो में तेल व्यापार करने के सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की सरकारों के प्रयासों को विफल कर दिया। सीरिया और यूक्रेन में लंबे समय तक युद्ध की वजह से, अमरीकी सैन्य–औद्योगिक क्षेत्र और उसके हथियारों का निर्यात बनाये रखा जाता है। इन क़दमों से रूस को कमजोर भी किया जाता है ।

पिछले 21 वर्षों के दौरान, दुनिया के विभिन्न देशों में विनाशकारी युद्धों के लिए, अमरीकी साम्राज्यवाद ज़िम्मेदार है। यह वही राज्य है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, सर्व–सम्मति से स्थापित किये गए, राज्यों के आपसी संबंधों के हर नियम और मानदंड का बार–बार उल्लंघन किया है। जब राष्ट्रपति बाइडन एक 'नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' के बारे में बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि अमरीकी साम्राज्यवाद यह मांग कर रहा है कि दुनिया के अन्य सभी राज्यों को अमरीका द्वारा दुनिया पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने और क़ायम रखने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/22587

11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमले के बाद से, पिछले 21 वर्षों की हक़ीक़त ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि आतंकवाद और तथाकथित आतंकवाद पर जंग, दोनों ही अमरीकी साम्राज्यवाद के हथकंडे हैं – उसकी प्रधानता को बरकरार रखने और उसके हुक्म तले एक ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने के उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए ।

असली मास्टरमाइंड?

कई पेशेवर इंजीनियरों ने बताया है कि न्यूयॉर्क में ट्विन–टावर विमानों के ऊपरी मंजिलों से टकराने से नहीं ढह सकते थे। जिस तरह से वे इमारतें ढह गईं थीं, उससे ऐसा लगता है कि इमारतों के स्टील के स्तंभों के नीचे बम विस्फोट किए गए होंगे। इतने बड़े कांड का अब तक भी कोई आधिकारिक जांच न होना इस संभावना की ओर इशारा करता है कि 11 सितम्बर के हमलों के पीछे असली मास्टरमाइंड अमरीकी राज्य के भीतर ही स्थित था।

15 सितम्बर 2022 को ए.आई.एल.आर.एस.ए. के नेतृत्व में रेल चालकों का दिल्ली डी.आर.एम. के सामने धरना प्रदर्शन

मज़दूर एकता लहर के लेखों को सुनिये

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) **पर जायें और ड्रॉपडाऊन मेनू या साइडबार में "लेखों को सुनें" पर क्लिक करें।**

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626,
ब्रांच नं.–00974, IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

बंटवारे के बाद के पचहत्तर साल :

हिन्दोस्तान के विभाजन के पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवादी रणनीति

1947 में उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक बंटवारे की भयानक वारदातों को हिन्दोस्तानी लोग कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि, इतिहास की किताबें इस विभाजन के वास्तविक उद्देश्य और, और यह क्यों हुआ, इनकी सच्चाई को छिपाती हैं। हिन्दोस्तानी शासक वर्ग के राजनेता उपमहाद्वीप के विभाजन के लिए पाकिस्तान के राजनेताओं को दोषी ठहराते हैं। वे इस सच्चाई को छिपाते हैं कि इस बंटवारे के मास्टरमाइंड ब्रिटिश साम्राज्यवादी ही थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हिन्दोस्तान के विभाजन को अपने हित में और संपूर्ण विश्व–साम्राज्यवाद के हितों में आयोजित किया था।

द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जैसे–जैसे नज़दीक आ रहा था, एशिया के उपनिवेशवादी और अर्ध–उपनिवेशवादी देशों के लोग, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी बोझ से अपनी मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली संघर्ष में उठ खड़े हुए थे। इनमें हिन्दोस्तानी लोगों के अलावा चीन, कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, फिलीपींस, ईरान, इराक और सीरिया के लोग भी शामिल थे। इनमें से कई देशों में मुक्ति संघर्षों का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया था।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को यह समझ में आने लगा था कि वे बहुत लंबे समय तक हिन्दोस्तान पर अपना सीधा शासन जारी नहीं रख सकते। विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही उन्होंने अपनी निकास–रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। मई 1945 में, "'हिन्दोस्तान और हिंद महासागर में ब्रिटिश साम्राज्य के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दीर्घकालिक नीति" पर युद्ध मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एशिया में उनके साम्राज्यवादी हितों के लिए समाजवादी सोवियत संघ को मुख्य ख़तरा मानते हुए, इस रिपोर्ट ने ब्रिटेन के लिए, हिन्दोस्तान के रणनीतिक महत्व के चार कारणों का हवाला दिया।

"एक सैनिक अड्डे के रूप में हिन्दोस्तान का स्थान, जहां से वहां पर तैनात किये गये सैनिक–बलों को न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में बल्कि मध्य–पूर्व और सुदूर–पूर्व क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है; वायु और समुद्री संचार के लिए एक पारगमन बिंदु; युद्ध के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाली जनशक्ति का एक बड़ा भंडार; और एक ऐसा देश जिस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, ब्रिटिश वायुशक्ति, सोवियत सैन्य–प्रतिष्ठानों के लिए ख़तरा पैदा कर सकती थी।"

(द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियास पार्टीशन – नरेंद्र सिंह सरिला, पृष्ठ 22)

1945–47 के दौरान, ब्रिटिश सशस्त्र बलों के मुखियों ने बार–बार उपमहाद्वीप के साथ, ब्रिटिश सैन्य संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर–पश्चिमी हिन्दोस्तान के महत्व पर जोर दिया। वे इस बात पर ज़ोर देते रहे कि हिन्दोस्तान के विभाजन से तेल–समृद्ध पश्चिम–एशिया और पूर्व और दक्षिण–पूर्व एशिया के क्षेत्रों में ब्रिटेन के रणनीतिक हितों की हिफाज़त होगी।

फरवरी 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने बगावत कर दी। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में मुंबई, कराची और कोलकाता के मज़दूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और नाविकों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। रॉयल इंडियन आर्मी के सैनिकों ने, नौसेना में अपने भाइयों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। नौसेना से लेकर थल सेना और वायु सेना में भी विद्रोह फैलने लगा। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उपमहाद्वीप से जाने से पहले हिन्दोस्तान के विभाजन की तैयारी तेज़ कर दी।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हिन्दोस्तान के स्वतंत्र होने के बाद, एशिया में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हिन्दोस्तान के विभाजन की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। क्रांति के लिए मज़दूरों, किसानों और बग़ावत कर रहे सैनिकों के डर से, हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग देश के विभाजन के लिए राज़ी हो गया।

सितंबर 1946 में, ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ ने "ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) के लिये हिन्दोस्तान का रणनीतिक महत्व" नाम की एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में फिर से एक बार दोहराया गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की हिफाज़त के लिए हिन्दोस्तान की जनशक्ति और क्षेत्र बहुत ही जरूरी थे। रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी संभावित–शत्रुतापूर्ण शक्ति को अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- फारस की खाड़ी से, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के लिए आवश्यक तेल और इसके यातायात के लिए एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- यदि एक शक्तिशाली वायु सेना के साथ रूस, हिन्दोस्तान पर हावी हो गया ... तो ब्रिटेन फ़ारस की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण खो देगा।
- हिन्दोस्तान हमारी साम्राज्यवादी रणनीतिक योजना की एक अनिवार्य कड़ी है।
- हिन्दोस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु युद्ध की संभावनाओं से खुली जगह की आवश्यकता बढ़ गई है और हिन्दोस्तान के पास यह जगह है।
- सुदूर–पूर्व में बड़े पैमाने पर राष्ट्रमंडल द्वारा सैन्य अभियान चलाने के लिए हिन्दोस्तान ही एकमात्र उपयुक्त सैन्य अड्डा है।
- सैन्य रणनीति के दृष्टिकोण से, हिन्दोस्तान की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक उसकी अपार जनशक्ति है।

(द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियास पार्टीशन – नरेंद्र सिंह सरिला, पृष्ठ 239–240)

उनके सामने सबसे अच्छे विकल्प के रूप में, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इस क्षेत्र में अपने सैन्य–दबदबे को स्थापित करने के लिए हिन्दोस्तान के विभाजन के साथ, एक सांप्रदायिक कत्लेआम आयोजित करने का फ़ैसला किया। अगस्त 1946 में कलकत्ता में सांप्रदायिक नरसंहार के आयोजन के बाद, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, एन.पी. ए. स्मिथ, ने वायसराय को लिखा :

"गंभीर साम्प्रदायिक अव्यवस्था की हालातों में, हमें ऐसी कार्रवाई कतई नहीं करनी चाहिए जो ब्रिटिश–विरोधी आंदोलन को फिर से शुरू कर दे। ऐसा आन्दोलन हमारे लिए एक बेहद ख़तरनाक स्थिति पैदा कर सकता है और हमारे लिए सभी रास्ते बंद करने की हालातें पैदा कर सकता है। सांप्रदायिक अव्यवस्था की हालातें एक तरह से स्वाभाविक हालांकि एक भयानक प्रक्रिया है, और ऐसी हालातें हिन्दोस्तान की समस्या के समाधान के लिए एक उचित तरीका भी हैं।"

ब्रिटिश खुफिया प्रमुख ने जिस ख़तरनाक स्थिति का जिक्र किया था, वह थी – हिन्दोस्तान के मज़दूरों और किसानों द्वारा क्रांति की संभावना। जिसका "समाधान" सांप्रदायिक–आधार पर हिन्दोस्तान का विभाजन था।

हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपति और बड़े जमींदार, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तुलना में, मज़दूरों और किसानों की क्रांति के और भी अधिक विरोधी थे। उन्होंने नौसेना के सैनिकों के विद्रोह की निंदा की। वे सत्ता को अपने हाथों में स्थानांतरित करने के लिए अंग्रेजों के साथ एक समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक थे।

साम्प्रदायिक विभाजन के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ अलग–अलग बातचीत की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दोनों पार्टियां उनकी साम्राज्यवादी विभाजन की योजना का, एक साथ मिल कर विरोध न करें, उनके बीच आपसी–संदेह को और भी बढ़ाने का काम किया। एक पार्टी को दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाते हुए, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने बहुत ही चालाकी से, सांप्रदायिक विभाजन को एक एकमात्र–विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। क्रांति की संभावनाओं को रोकने और अपने हाथों में सत्ता हासिल करने की उत्सुकता में, हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के प्रतिद्वंदी गुट ब्रिटिश साम्राज्यवादी विभाजन की योजना के साथ सहमत हुए।

हिन्दोस्तान के विभाजन ने, हिन्दोस्तान के उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान के रूप में एक विश्वसनीय सैन्य अड्डा प्रदान करके, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रणनीति को सफल बनाया।

शीत युद्ध की अवधि के दौरान, अपने खुदगर्ज़ हितों की हिफाज़त के लिए, एंग्लो–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि हिन्दोस्तान और पाकिस्तान हमेशा एक–दूसरे के दुश्मन बने रहे।

शीत युद्ध की अवधि के दौरान, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जिसमें 1971 में एक सैन्य संधि पर हस्ताक्षर करना भी शामिल है। अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने, अमरीका और सोवियत संघ के बीच टकराव का फायदा उठाया। पाकिस्तान के शासक वर्ग ने, ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवादियों को अपने देश में सैन्य–अड्डे प्रदान किए। सेंट्रल ट्रीटि आर्गेनाइजेशन (सी.ई.एन.टी.ओ.) और साउथ एशिया ट्रीटि आर्गेनाइजेशन (एस.ई.ए.टी.ओ.) के अमरीकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में पाकिस्तान शामिल हो गया। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत सेना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एक पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया।

सोवियत संघ के पतन के बाद, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने पाकिस्तान का इस्तेमाल आतंकवादी गुटों के एक प्रजनन–स्थल (ब्रीडिंग ग्राउंड) के रूप में किया जिन्हें दुनियाभर में तैनात किया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद का स्रोत होने का आरोप लगाया – इस सच्चाई को छिपाते हुए कि यह अमरीका ही था जिसने इन आतंकवादी–गुटों को बनाया था। दशकों से चले आ रहे पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए रास्ते ने, उसके अपने देश के अंदरूनी मामलों में अमरीकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया है, जिसके विनाशकारी परिणाम पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं।

शीत युद्ध के बाद की अवधि में, अमरीका सुनियोजित रूप से हिन्दोस्तान के साथ रणनीतिक–सैन्य गठबंधन बना रहा है और मजबूत कर रहा है। चीन सहित अन्य एशियाई देशों के लोगों के ख़िलाफ़, अमरीका, हिन्दोस्तान की धरती और यहां रहने वाले लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि पूरे एशिया को अपने प्रभुत्व में लाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।

निष्कर्ष

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हिन्दोस्तान के स्वतंत्र होने के बाद, एशिया में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हिन्दोस्तान के विभाजन की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। क्रांति के लिए मज़दूरों, किसानों और बग़ावत कर रहे सैनिकों के डर से, हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग देश के विभाजन के लिए राज़ी हो गया।

हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा किए गए विभाजन से कोई सबक नहीं सीखा है। अपने संकीर्ण खुदगर्ज़ साम्राज्यवादी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, हमारे देश का शासक वर्ग हिन्दोस्तान की संप्रभुता और इस पूरे क्षेत्र में शांति को ख़तरे में डाल रहा है। यह अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ एक ख़तरनाक रणनीतिक–सैन्य साझेदारी कायम करने के इरादे से काम कर रहा है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमारे लोगों को एक विनाशकारी युद्ध में फंसा सकता है।

http://hindi.cgpi.org/22580

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org, **अंग्रेजी** : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org, **तामिल** : http://www.tamil.cgpi.org
ई मेल : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Sep, 2022 Date of publish - 16 Sep, 2022

To .....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में अमरीकी साम्राज्यवाद का बढ़ता सैन्यीकरण

अमरीकी नौसेना ने 29 जून से 4 अगस्त, 2022 के बीच, प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप के तट पर दुनिया के सबसे बड़े समुद्री युद्ध अभ्यास की मेज़बानी की।

इस समुद्री युद्ध अभ्यास को रिमपैक के नाम से जाना जाता है। इसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें अमरीका के अलावा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, हिन्दोस्तान, ब्रूनेई, चिले, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इस्राइल, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और टोंगा शामिल थे।

38 जहाज, 4 पनडुब्बियां, 9 देशों की राष्ट्रीय सेनाएं, 170 से अधिक विमान सहित लगभग 25,000 सैन्य कर्मियों ने हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में और उसके आसपास एक साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। अमरीका के नेतृत्व में सैन्य सहयोग और समन्वय का यह एक विशाल प्रदर्शन था और स्पष्ट रूप से चीन के ख़िलाफ़ संदेश था।

1971 से अमरीका के नेतृत्व में सैन्य रिमपैक अभ्यास हर दूसरे साल में आयोजित किया जा रहा है। यह अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सैन्य युद्ध अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। अमरीका 1974 से इसमें अन्य देशों को शामिल कर रहा है। पिछली बार, 2018 में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। 2020 में कोविड–19 महामारी के कारण, रिमपैक सिर्फ समुद्री युद्ध अभ्यास था।

इससे पहले चीन को भी रिमपैक में आमंत्रित किया गया था। चीन ने 2014 और

2016 में रिमपैक में हिस्सा लिया था। मई 2018 में, अमरीका के रक्षा संगठन पेंटागन ने चीन को पहले आमंत्रित किया और बाद में रिमपैक में भाग लेने के निमंत्रण को रद्द कर दिया। यह चीन को खुले तौर पर निशाना बनाने के अमरीका के निर्णय को दर्शाता है। अमरीका एशिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य के लिए चीन को मुख्य बाधा के रूप में देखता है। निमंत्रण को रद्द किए जाने का कारण बताया गया कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के चलते चीन और अन्य कुछ एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय दावों के विवाद हैं।

दिसंबर 2021 में, अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एन.डी.ए.ए.) पारित किया, जिसमें बाइडन प्रशासन ने सिफ़ारिश की कि ताइवान को रिमपैक में आमंत्रित किया जाए जो चीन के ख़िलाफ़ एक स्पष्ट उकसावा था। लेकिन अंततः ताइवान को रिमपैक 2022 में आमंत्रित नहीं किया गया था, इस प्रकार चीन के साथ अमरीका का टकराव और तेज होने से बच गया।

लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस साल जुलाई के मध्य में, जब रिमपैक 2022 अभ्यास चल ही रहा था तभी अमरीका ने चीन की समुद्री तट रेखा पर, ताइवान समुद्र–संधि के जरिए अपने युद्ध पोतों को भेजकर, चीन के ख़िलाफ़ एक सैन्य उकसावे को अंजाम दिया।

2006 से रिमपैक में हिन्दोस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था। हिन्दोस्तान ने पहली बार रिमपैक 2014 में भाग लिया था। तब से, यह लगातार रिमपैक में हिस्सा ले रहा है। इन रिमपैक कार्यवाहियों में आई.एन.एस. सह्याद्री और आई.एन.एस. सतपुरा नामक नौसेना की जंगी जहाजों के बेड़े ने हिस्सा लिया है। इनके अलावा, रिमपैक 2022 में हिन्दोस्तानी सशस्त्र बलों ने हिन्दोस्तानी नौसेना के लिए बोइंग द्वारा निर्मित किए जा रहे पी–81 लंबी दूरी, बहु–मिशन समुद्री गश्ती विमान के साथ हिस्सा लिया। पी–81 में पनडुब्बी–रोधी युद्ध (ए.एस.डब्ल्यू.), सतह–रोधी युद्ध (ए.एस.यू.डब्ल्यू.), खुफ़िया तंत्र, समुद्री गश्त और निगरानी मिशन के लिए उन्नत क्षमताएं होने की सूचना है।

रिमपैक 2022 अभ्यासों को इस पूरे क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अमरीका द्वारा अपनाई गई रणनीति के दृष्टिकोण में देखा जाना चाहिए। अमरीका चीन की प्रगति को रोकना चाहता है। चीन हाल के वर्षों में अमरीका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चीन के ख़िलाफ़ बार–बार उकसाने की कार्रवाई के साथ, दक्षिण चीन सागर में अमरीकी सैन्य बलों की तैनाती का दायरा में वृद्धि हुई है। अमरीका हिन्दोस्तान और अन्य देशों को चीन के ख़िलाफ़ भड़काता भी रहा है।

अमरीका हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के प्रयासों में हिन्दोस्तान को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है। इस दिशा में, अमरीकी साम्राज्यवादी हिन्दोस्तानी शासक वर्ग के साथ एक सैन्य रणनीतिक गठबंधन का निर्माण करने के साथ–साथ मजबूती प्रदान करते आ रहे हैं। अमरीका पूरे एशिया को अपने प्रभुत्व में लाने के उद्देश्य को साकार करने के लिए एशिया के अन्य देशों के लोगों के ख़िलाफ़ हिन्दोस्तान की धरती और लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है।

अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा हिंद–प्रशांत का सैन्यीकरण इस क्षेत्र में शांति के लिए ख़तरनाक है। हिन्दोस्तानी लोगों को इस सैन्यीकरण का विरोध करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि हिन्दोस्तान अमरीका के साथ अपने सैन्य गठबंधन को तोड़ दे।

http://hindi.cgpi.org/22582

अमरीकी रणनीति में हिन्दोस्तान

पृष्ठ 1 का शेष

हिन्दोस्तान को विभिन्न देशों के लोगों को अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने से रोकने और चीन के प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को रोकने के 'बोझ' को उठाने में अमरीका का सांझेदार बनना चाहिए।

चीन पिछले दो दशकों में अमरीका के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। अमरीका, चीन की प्रगति को रोकना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, वह हिन्दोस्तान को सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक के रूप में देखता है। हिन्दोस्तान की इस भूमिका को हासिल करने के लिए, अमरीका खास कर पूर्व की दिशा में हिन्दोस्तान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे रहा है। हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीवादी घराने अपने बाज़ारों और कच्चे माल के स्रोतों को बढ़ाने और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की नयी–नयी संभावनाओं से बेहद उत्साहित हैं। वे अमरीकी साम्राज्यवादियों के साथ सहयोग और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के ज़रिए ऐसा करने का सपना देख रहे हैं।

पिछले दो दशकों में, अमरीकी साम्राज्यवादी क्रमशः हिन्दोस्तानी शासक वर्ग के साथ सैन्य–रणनीतिक गठबंधन बनाते जा रहे हैं और उसे मजबूत कर रहे हैं। अमरीका पूरे एशिया को अपने प्रभुत्व में लाने के अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए, हिन्दोस्तान के क्षेत्र और लोगों को एशिया के अन्य देशों के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है।

हिन्दोस्तानी राज्य ने अमरीका के साथ कई सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से इस बात की संभावना बनती है कि अमरीका इस क्षेत्र में अपने युद्धों के लिए हिन्दोस्तान को अपने सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हिन्दोस्तान का शासक वर्ग अपने तंग साम्राज्यवादी मंसूबों को हासिल करने के लिए, देश की संप्रभुता और इस क्षेत्र में शांति को ख़तरे में डाल रहा है। वह एक ख़तरनाक रास्ते पर चल रहा है जो हमारे लोगों और देश को विनाशकारी युद्ध में धकेल सकता है।

अमरीका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने के साथ–साथ, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने रूस के साथ भी अपना सैनिक–रणनीतिक संबंध बना रखा है। हिन्दोस्तानी शासक वर्ग इन संबंधों को बनाए रखने में कई फ़ायदे देखता है। हिन्दोस्तानी सेना को ऐतिहासिक तौर पर, रूस से अत्याधुनिक हथियार प्राप्त होते रहे हैं। इन हथियारों की देखरेख के लिए हिन्दोस्तान रूस पर निर्भर है। इसके अलावा, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग रूस के साथ समन्वय करके, हिन्दोस्तान के उत्तर पश्चिम की ओर – ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों में अपने हितों को बढ़ावा देने की उम्मीद करता है। वह रूस के साथ अपने संबंधों को नष्ट नहीं करना चाहता है, जैसा कि अमरीका मांग कर रहा है। यह इस बात से साफ़–साफ़ नज़र आता है कि हिन्दोस्तानी राज्य ने, अमरीका की मांगों के बावजूद, यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस की निंदा करने या रूस पर प्रतिबंध लगाये जाने को जायज़ ठहराने से इनकार किया है। इस समय, अमरीका हिन्दोस्तान को रूस के साथ संबंधों के मामले में काफी लम्बी छूट दे रहा है। अमरीका चीन को अलग–थलग और कमजोर करने के अपने उद्देश्य में हिन्दोस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। अमरीकी साम्राज्यवादी चीन के ख़िलाफ़ एक के बाद एक उकसाने वाली हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं और वे हिन्दोस्तान पर भी ऐसा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमरीका जिस रास्ते पर चल रहा है, उसके परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र में युद्ध या एक और विश्व युद्ध हो सकता है।

हिन्दोस्तानी शासक वर्ग एक खतरनाक रास्ता अपना रहा है। हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग और लोगों को अमरीकी साम्राज्यवाद की एशिया पर अपना प्रभुत्व जमाने की रणनीति में, हिन्दोस्तान की भागीदारी का विरोध करना चाहिए। हमें अमरीका के साथ हिन्दोस्तान के सैनिक–रणनीतिक गठबंधन को तोड़ने की मांग करनी चाहिए और इसके लिए संघर्ष करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22590